साप्ताहिक

जागत गाँव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 02-08 जनवरी, 2023 वर्ष-8, अंक-38 | भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित | पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

प्रदेश के लिए उपलब्धियों-नवाचारों का साल रहा 2022

पशुपालन की योजनाओं में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश

भोपाल। पशुपालन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। अन्य राज्यों के लिए मध्यप्रदेश मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 2 करोड़ 92 लाख 51 हजार गौ-भैंस वंशीय पशु पंजीकृत हैं। इन पशुओं को यूआईडी टैग लगा कर इनॉफ पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। एफएमडी (मुंहपका खुरपका रोग) टीकाकरण में भी मप्र देश में प्रथम है। प्रदेश में पहले चरण में 2 करोड़ 50 लाख 63 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। माह नवंबर के प्रथम सप्ताह तक 36 लाख 14 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया। मप्र ब्रूसेला टीकाकरण में भी देश में शीर्ष पर है। पहले चरण में 4 से 8 माह की 17 लाख 45 हजार गौ-भैंस वंशीय बछियों का टीकाकरण किया गया। दूसरे चरण में 7 नवंबर 2022 तक 39 जिलों के 10 लाख 50 हजार बछियों का टीकाकरण किया जाकर इनॉफ (इंफारमेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एण्ड हेल्थ) पोर्टल में जानकारी दर्ज की जा चुकी है।

क्रेडिट कार्ड सुविधा बढ़ी

केन्द्र द्वारा पशुपालन और मत्स्य व्यवसायिक किसानों की आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार में मप्र प्रथम स्थान पर है। 2 दिसम्बर तक प्रदेश के 2 लाख 5 हजार 70 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए। पशुपालकों को सहकारी बैंकों से शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्र से मिला अनुदान

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम में बकरी, सूकर, मुर्गी पालन और चरी-चारा के लगभग 1860 से अधिक प्रस्ताव विभाग को ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 27 प्रकरणों में केन्द्र सरकार से अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र ने तैयार किया मॉडल

इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से आत्मनिर्भर होंगे किसान

केंद्र ने भी सराहा और कृषि पत्रिका में जगह दी

जागत गांव हमार, शिवपुरी। खेमराज मौर्य

कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी ने किसान के खेत को दुकान बनाने का माडल तैयार किया है। इस माडल पर आधारित खेती करके किसान न सिर्फ पारंपरिक खेती कर सकेगा, बल्कि खेत से ही मुर्गा फार्म, दूध डेयरी, मछली फार्म के संचालन सहित फल-फूल की बिक्री कर सकेगा। इससे किसान का खेत एक दुकान का रूप ले लेगा। कृषि विज्ञान केंद्र ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत खेती) सिस्टम बनाया है। इसमें खेत को अलग-अलग छह हिस्सों में बांटकर खेती की जाती है। बड़े हिस्से में मूल फसल लगाई जाती है और शेष अन्य पांच हिस्सों में दूसरी फसलें और पशु पालन किया जाता है। इसमें किसान के खेत में छोटा सा तालाब भी बनाया जाता है, जिससे बारिश का पानी एकत्रित करने के साथ मछली पालन किया जा सके। इसी के ऊपर बने ओवरहेड में मुर्गी पालन होता है। जब इस पानी से खेत की सिंचाई की जाती है तो कम खाद की आवश्यकता होती है। सिर्फ शिवपुरी ही नहीं, बल्कि ग्वालियर-चंबल के कई किसानों ने इस मॉडल को अपनाया है। इसका प्रस्तुतीकरण देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने एक हेक्टेयर में ऐसा खेत भी तैयार किया है। इस मॉडल से किसान एक हेक्टेयर में 95200 रुपए की लागत में 186500 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर सकता है। इस मॉडल को केंद्र सरकार ने भी सराहा है और अपनी कृषि पत्रिका में जगह दी है।

पानी पर ओवर हेड शेड

वैज्ञानिकों के अनुसार एक हेक्टेयर के खेत में 30 बाय 28 मीटर के क्षेत्रफल में 2.1 मीटर गहराई का तालाब बनाया जाता है। तालाब में वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। इस तालाब के किनारे पानी के ऊपर एक ओवर हेड शेड तैयार करवाया गया है जिसमें मुर्गा-मुर्गी, खरगोश आदि पाले जाते हैं जबकि तालाब में मछली पालन किया जाता है। ओवरहेड शेड में जो जाना दाना मुर्गा, मुर्गी के लिए दिया जाता है, उसमें से जो दाना नीचे तालाब में गिरता है उसे मछलियां अपना भोजन बनाती हैं। मुर्गियों के मलमूत्र से पानी में खाद के तत्व समाहित होते हैं।

अवयव	क्षेत्र	क्षेत्र का प्रतिशत	लागत	सकल आय	शुद्ध आय
फसल उत्पादन	0.4	40	16800	27800	11000
चारा उत्पादन	0.2	20	8400	13900	5500
सब्जी उत्पादन	0.1	10	36000	90000	54000
फूल उत्पादन	0.1	10	8000	40000	32000
फल उत्पादन	0.1	10	6000	20000	14000
मछली उत्पादन	0.1	10	20000	90000	70000
कुल रकबा	1.0	100	95200	281700	186500

(नोट- यह विज्ञान केंद्र द्वारा एक हेक्टेयर में बनाए गए मॉडल के आधार पर है।)

किसानों ने मुनाफा बढ़ाया

रातौर के किसान पदम सिंह धाकड़ ने बताया कि उसके खेत में पहले ही तालाब था। उसने तालाब के चारों तरफ किनारे पर आम, अमरुद, नींबू आदि के जल्द फल देने वाले पौधे रोपे हैं, जिनकी जड़े तालाब से पोषित होती हैं। नरवर के समोहा गांव के रहने वाले किसान बहादुर सिंह रावत ने बताया कि उसे पांच हेक्टेयर में लगभग 80 प्रतिशत इस माडल को अपना लिया है और मुनाफा भी बढ़ा है। जल्द ही अधिक बड़े क्षेत्र में इस तरह खेती करेंगे।

ऐसे हुआ लागत का दोगुना लाभ

हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल तैयार किया है। हमारे इस मॉडल से प्रेरित होकर कई किसान मॉडल को पूरा या फिर आधा अपना रहे हैं जिससे किसानों की आय बढ़ी है। लागत का दोगुना लाभ अर्जित किया है। इस मॉडल से छोटे किसानों के घर के किसी भी सदस्य को मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकता है। मॉडल में और सुधार कर रहे हैं।

डॉ. एमके भार्गव,
वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

-24 गांव की 20 हजार एकड़ भूमि होगी सिंचित

सीहोर के चार हजार किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास की गति को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। किसानों के हित में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। सीहोर जिले के ग्राम डोबी में 106 करोड़ 35 लाख रूपये की लागत वाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया गया है। परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इससे 24 गांव की 20 हजार एकड़ कृषि भूमि सिंचित होगी। परियोजना से 4 हजार किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ग्राम डोबी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्वहन सिंचाई परियोजना से ग्रामीणों के खेतों में पानी पहुंचेगा, जिससे किसान को अच्छी फसल के साथ अच्छी आय भी होगी। किसानों के हित में राज्य सरकार अनेक योजनाएं भी संचालित कर रही हैं। किसानों की उन्नति और विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं।

हर खेत पहुंचेगा पानी

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों और किसानों की मांग को सहज स्वीकारते हुए मंच से परियोजना में अन्य ग्रामों को जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलग मंजूर किए जाएंगे। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा कर फसलों की पैदावार बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस परियोजना से अंतिम छोर के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा।

सकारात्मक बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो स्व-सहायता समूहों से जुड़े कर महिलाएं आत्म-निर्भर बन रही है। इससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज हमारी बहनें आत्म-निर्भर बन कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। स्व-सहायता समूह को बैंक लिंकेज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरी हर बहन की आय 10 हजार रुपए प्रति माह हो, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं।

पुरातत्व विभाग के किले को पर्यटन बोर्ड को दिए जाने से बनी स्थिति

चिंता: संकट में प्रदेश के इकलौते सहरिया संग्रहालय का अस्तित्व

भोपाल। श्योपुर के ऐतिहासिक किले को पर्यटन बोर्ड को दिया जा रहा है। ऐसे में किले में संचालित प्रदेश के इकलौते सहरिया संग्रहालय के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यटन बोर्ड किले को निजी हाथों में सौंपेगा, लिहाजा संग्रहालय यहां से हटाना पड़ेगा, लेकिन यहां बनी सहरिया जनजाति की कलाकृतियां फिर से दूसरी जगह बनाना आसान नहीं है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है कि अब सहरिया संग्रहालय का क्या होगा। बताया गया है कि

पुरातत्व विभाग के अधीन रहे श्योपुर किले का ऊपरी हिस्सा अब मप्र पर्यटन बोर्ड को दिया जा रहा है। जिसके बाद पर्यटन बोर्ड इसे निजी हाथों में दे देगा।

हालांकि वर्ष 2018 में भी इस प्रकार की कवायद हुई थी, लेकिन उस समय विरोध के चलते ये निर्णय वापस हो गया। लेकिन अब किले को पर्यटन बोर्ड को देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि संग्रहालय वाला भवन भी निजी हाथों में गया तो फिर संग्रहालय को कहां शिफ्ट किया जाएगा।

1986 में बनी परिकल्पना

सहरिया जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति रही है, जिसे संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से सहरिया विकास अभिकरण, नगरपालिका श्योपुर और पुरातत्व संरक्षण समिति के माध्यम से सहरिया संग्रहालय के रूप में फ्रेम किया गया है। ग्वालियर-चंबल के तत्कालीन कमिश्नर और सहरिया विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष अजय शंकर ने वर्ष 1986 में इसकी परिकल्पना की और पुरातत्व संरक्षण समिति बनाई। समिति ने जिले के सहरिया गांवों में पहुंचकर न केवल अध्ययन किया बल्कि सहरिया संस्कृति से जुड़ी सामग्री संकलित की। जिसके बाद वर्ष 1990 में श्योपुर किला स्थित बड़े भवन में सहरिया संग्रहालय स्थापित किया गया।

अहीर धामनोद के सब्जी उत्पादक किसान का प्रयोग बना लाभकारी

किसान के नवाचार ने फसलों को वायरस अटैक से बचाया

जागत गांव हमार, खरगोन। संजय शर्मा

अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में रसायनों का छिड़काव से खाद्य उत्पादन की शुद्धता तो प्रभावित होती ही है। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ-साथ फसलों होने वाली पर अनावश्यक रोग बीमारियों से भी पड़ता है। साथ ही अत्यधिक कीटनाशकों के छिड़काव से फसल लागत पर तो पड़ता ही है। इन सब प्रभावों से बचने के लिए कसरावद जनपद में अहिर धामनोद के किसान नवाचार कर ऐसी मुसीबतों से बचने का विकल्प चुना है। यहां के संजय राठौर और उनके भाई नवल राठौर तथा गिरधारी और देवराम राठौर क्रॉप कवर का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। संजय राठौर ने बताया कि 4 वर्षों से क्रॉप कवर का उपयोग कर मिर्च, करेला और गिलकी की सब्जी में करते आ रहे हैं। इसके उपयोग से वायरस का अटैक नहीं हो पाया है। किसानों को क्रॉप कवर का सबसे ज्यादा लाभ वायरस अटैक से बचने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

कीटनाशक छिड़काव की हुई बचत

अहिर धामनोद के 45 वर्षीय नवल राठौर ने बताया कि क्रॉप कवर नहीं बल्कि ये गरीब किसानों के लिए ये मिनी पॉली हॉउस है। इसके उपगोग से वो 80 से 85 प्रतिशत तक छिड़काव कम कर दिया है। पिछले 3 वर्षों से वे गिलकी, मिर्च और करेला में प्रमुखता से इस विकल्प का प्रयोग कर अच्छा खासा मुनाफा और ज्यादा उत्पादन ले पा रहे हैं। नवल के ही छोटे भाई संजय ने बताया कि पिछले वर्ष करेला की फसल से कवर उड़ जाने से करीब 4 से 5 लाइन के उत्पादन क्षमता और बहुत ज्यादा फर्क देखा। इससे भी उन्हें कवर और बिना कवर की फसल में मुनाफे में अंतर मालूम हुआ।

क्रॉप कवर के फायदे

संजय राठौर के अनुसार क्रॉप कवर सुरक्षा कवच से कम नहीं है। यह कवर पौधों को कीटों और धूप से बचाने के साथ ही उन्हें तेज धूप में जलने से बचाता है। इसके साथ ही 45 डिग्री तापमान में भी पौधों के आसपास नमी बनाए रखता है। पौधे की ऊंचाई 5 फीट तक होने तक पौधे को क्रॉप कवर में रखा जा सकता है। इस तकनीक के अपनाने से पारा 10 से 15 डिग्री तक कम हो जाता है। क्रॉप कवर से किसी प्रकार के कीट पौधे को नुकसान नहीं पहुंचते ।कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम होता है।

ठेमा गांव की दुर्गा दूसरी महिलाओं के लिए बनीं आदर्श

फसल के साथ-साथ फलों की खेती

अमरूद की खेती से आगे बढ़ रहीं आसपास की महिलाएं

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट।

खेती को लाभ का धंधा बनाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब किसानों द्वारा खेती के नये नये गुर सीखे जा रहे हैं और इसमें महिला किसान भी बढ़चढ़ कर आगे आ रही हैं, जो फसल के साथ साथ फलों की भी खेती कर रही है और खेती से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है।

दरअसल, बालाघाट जिले के लांजी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम ठेमा की रहने वाली दुर्गा कुराहे इन दिनो अमरूद की खेती कर रही हैं, जिसके बलबूते उसने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सपना भी साकार कर लिया है। महिला कृषक दुर्गा करहिे ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते उसने स्व-सहायता समूह से लोन लिया और पिछले तीन सालों से वह अमरूद की खेती कर रही हैं। जिससे अब वह हजारों रुपए भी कमा रही है। इससे ना सिर्फ कृषि क्षेत्र में उसकी रुचि बढ़ी है, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। अब ठेमा निवासी दुर्गा करहिे अन्य दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी बन चुकी हैं।

अमरूद पर किया फोकस

बताया जा रहा है कि महिला किसान दुर्गा करहिे ने आज से तीन पहले महिलाओं का एक समूह बनाया था। जहां शक्ति आजीविका स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष दुर्गा कुराहे ने वर्ष 2018 में समूह का गठन किया था। जिसके बाद उसने बचत शुरू की और इस समूह से समय समय पर छोटी छोटी राशि ऋण लिया और फिर उन पैसों से अपने खेत में बोर करवाया। साथ ही खेती को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्र खरीदे और सीजन वार फसल लगाना शुरू किया। जहां उसने अमरूद की खेती को ज्यादा प्राथमिकता दी।

खेत के साथ घरों में लगाए पौधे

जहां अमरुद की फसल ने न केवल जिंदगी बदल दी, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर दिया। दुर्गा करहिे पिछले तीन वर्षों से लगातार अमरुद की खेती करते हुए अच्छी आय प्राप्त करने लगी और ऐसा करके उसने एक मिशाल भी पेश की है। दुर्गा कुराहे ने बताया कि आजीविका मिशन के माध्यम से 100 पौधे थाई अमरुद के प्राप्त किए। इसके अलावा आम्रपाली आम के पौधे भी प्राप्त किए। जहां उसने आम व अमरूद के पौधों को अपने खेत व समूह की महिलओं के घरों व खेतों में रोपा।

जीवन में आई खुशहाली

थाई अमरुद के पौधे रोपने के बाद उनकी देखरेख भी की। जहां अमरुद के पौधों में केवल 6 माह में ही फल लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दुर्गा पिछले तीन वर्षों से यह कार्य कर रही हैं। अमरुद के पौधों में वर्तमान में फल लग गए हैं। फलों का आकार 500 से 750 ग्राम तक है। अमरुद की खेती से दुर्गा की न केवल आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, बल्कि वह अपने पति व बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जो अपने आप में एक मिसाल है और अन्य महिलाओं के लिए आदर्श भी।

केवीके में महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया

बताया कैसे बनाएं जीवामृत बीजामृत और घन जीवामृत

जागत गांव हमार, बैतूल।

कृषि विज्ञान केन्द्र, में प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिरडी संस्थान के विभिन्न महिला समूह शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉ. मेघा दुबे द्वारा प्राकृतिक खेती के महत्व एवं उसमें उपयोग होने वाले विभिन्न अव्यव जैसे- जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, दषपर्णी, नीमास्त्र आदि को बनाने की विधि एवं प्रयोग करने के तरीकों के बारे में बताया गया। साथ ही केन्द्र की प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण इकाई एवं केन्द्र पर लगाए गए प्रदर्शन इकाई का भ्रमण कराया गया। डॉ. एमपी इंगले, खाद्य वैज्ञानिक द्वारा मशरूम उत्पादन एवं मशरूम का मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण दिया गया जिसमें मशरूम का अचार बनाया गया। इस कार्यक्रम में केन्द्र के प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा द्वारा प्राकृतिक खेती के पंजीयन एवं इसको बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा कोदो, कुटकी, रागी, सावा आदि की खेती करने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप बीएल बिलैया, संयुक्त संचालक कृषि, नर्मदापुरम, आरजी रजक, उपसंचालक कृषि बैतूल, आरके कोरी, उपसंचालक उद्यान बैतूल एवं अन्य वैज्ञानिक उपस्थित थे।

बीज के लिए जबलपुर उत्तरप्रदेश के जालौन और इटावा जिलों पर आश्रित

अच्छे बीज को मोहताज देशभर को मटर खिलाने वाला जबलपुर जिला

जागत गांव हमार, जबलपुर। प्रवीन नामदेव

देशभर में मटर उत्पादन के लिए जबलपुर जिला प्रसिद्ध है। यहां से देश के कोने-कोने में उन्नत गुणवत्ता का हरा-मटर सप्लाई होता है। वहीं इस हकीकत को कम ही लोग जानते हैं कि जबलपुर का जो मटर देशभर में लाखों रसोई की शान बढ़ाता है, उस मटर का बीज यहां तैयार नहीं होता। बीज के लिए जबलपुर उत्तरप्रदेश के जालौन और इटावा जिलों पर आश्रित है। कुछ किसान छिंदवाड़ा से भी बीज मंगाते हैं। पूरे सीजन में जिले में तीन लाख टन से अधिक मटर का उत्पादन होता है। हालांकि प्रशासन यहां बीज उत्पादन का रास्ता तलाशने की दिशा में काम करने की बात कह रहा है। दरअसल, जबलपुर जिले में तैयार होने वाले मटर के बीज की उत्पादकता बहुत नहीं होती। किसानों का कहना है कि यहां तैयार हुए बीज की उपज जालौन, उन्नाव और इटावा से आए बीजों की अपेक्षा कमजोर होती है, इसलिए वो स्थानीय बीजों का उपयोग नहीं करते। किसानों का दावा है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान उन्नाव, जालौन और इटावा के बीज का इस्तेमाल करते हैं।

किसानों से उलट विज्ञानियों का दावा

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानी डॉ. एके सिंह ने बताया कि मटर का ब्रीडर-शीड उनके यहां ही तैयार किया जाता है। इसके बाद वो उसे कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम जैसे सरकारी संस्थानों को ये ब्रीडर-शीड कृषि विभाग और राष्ट्रीय बीज निगम को दे देता है। जो अपने-अपने प्रक्षेत्रों में ब्रीडर शीड्स का इस्तेमाल कर वो बीज तैयार करता है जो किसानों को बोवनी के लिए दिया जाता है। डॉ. सिंह का दावा है कि सर्टिफाइड-2 बीज से किसान खुद भी दो बार बीज तैयार कर सकता है।

जबलपुर में बीज तैयार तो होते हैं,लेकिन उन बीजों की उत्पादकता सामान्य ही होती है। इसलिए क्षेत्र के किसान यहां के लोकल-बीज का उपयोग नहीं करते।
-अर्श पटेल, किसान-कुसमी

जिले के 80 प्रतिशत किसान दूसरे उत्तरप्रदेश के बीजों पर आश्रित हैं। जालौन और इटावा से आने वाला बीज जबलपुर में तैयार किए गए बीज से अच्छा है।
-नंदकिशोर पटैल, किसान-नगना

जबलपुर सहित प्रदेश के तमाम जिलों में मटर-बीज उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों से ही आता है। वहां के बीज की गुणवत्ता यहां के मुकाबले बहुत उत्कृष्ट है।
-देवेंद्र श्रीवास्तव, काश्तकार-सिहोरा

उन्नत श्रेणी के बीज तैयार करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र औ एनएससी द्वारा बीज-तैयार किया जाता है। इस मामले में सतत शोध जारी हैं।
-डॉ. नेहा पटैल, उप-संचालक उद्यानिकी

खेती के मास्टर बने इंदौर के किसान

खेत से ही खड़ा किया हल्दी का बाजार

-मेहनत और कौशल से लिख रहे इबारत

इंदौर। वे मिट्टी से लोहा लेकर सोना उपजा रहे हैं। परंपरागत खेती को छोड़ कर नए-नए प्रयोग करने में जुटे हैं और खुद ही खेती के मास्टर बन रहे हैं। अपनी मेहनत और कौशल से घाटे की कृषि को अलविदा कहकर इसे लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। जैविक खेती को अपनाकर किसी किसान ने कृषि उत्पादों को सीधे उपभोक्ता के घर पहुंचाना शुरू किया है तो किसी ने फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीओ) बनाकर किसानों के उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम शुरू किया है। किसानों की आय बढ़ने लगी है और अन्य किसानों के लिए भी मिसाल बनते जा रहे हैं। सिमरोल के युवा किसान जितेंद्र पाटीदार ने परंपरागत खेती करते-करते चार साल से जैविक हल्दी की खेती शुरू की है। इन चार सालों में उन्होंने इतनी विश्वसनीयता बनाई है कि खुद के खेत पर उगाई गई हल्दी का पाउडर खास उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। जितेंद्र खेती के सारे तकनीक पक्ष देखते हैं तो उनकी मां निशा पाटीदार और पत्नी प्रियंका पाटीदार हल्दी की प्रोसेसिंग करके पाउडर तैयार करती हैं। अपने खेत पर उगाई जाने वाली अरहर, मूंग, उड़द से वे घट्टी की दाल तैयार करते हैं। जितेंद्र ने इस साल बिल्कुल अलग प्रयोग किया है। हल्दी की फसल के साथ ट्रैप क्रॉप के रूप में निमाड़ में होने वाली अंबाड़ी की फसल लगाई है। वे बताते हैं, इससे हल्दी पर कीट नहीं लगेंगे। खेती को उद्यम के रूप में अपनाने वाले जितेंद्र आसपास के गांवों का क्लस्टर तैयार कर किसानों की ही कंपनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

सब्जी, दाल, अनाज सब जैविक

इंदौर जिले के उमरिया खुर्द गांव के किसान आनंदसिंह ठाकुर ने करीब 19 साल से अपने खेतों पर रासायनिक दवाओं और रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दिया है। वे गोबर की खाद और अन्य जैविक उपाय अपनाकर सब्जियां, दालें और अनाज पैदा कर रहे हैं। अपनी 17 एकड़ की खेती में मेड़ों पर ही उन्होंने अमरूद, संतरा, आम, कटहल, नींबू के करीब 500 फलदार पेड़ लगाए हैं। ठाकुर बताते हैं, जब पहली बार जैविक खेती शुरू की तो पहले शुरुआत में 10-15 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ, लेकिन बाद में जैविक खाद से जमीन उपजाऊ होने के बाद पैदावार बढ़ गई। आज इस जमीन से मुझे सालाना लगभग 18 लाख रुपये की फसल मिल रही है। पहले खेत पर तैयार होने वाले उत्पादों की दो साल तक होम डिलिवरी की और अब बायपास रोड पर जैविक सेतु के माध्यम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं। खेती में उनकी पत्नी और बेटे का भी पूरा सहयोग रहता है।

इतिहास से बना रहे खेती का समाजशास्त्र

इंदौर जिले के ही हरसोला गांव के महेश राठौर ने इतिहास, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र में एमए किया है। अब खेती के प्राचीन इतिहास से फसलों का आधुनिक समाजशास्त्र तैयार करने में जुटे हैं। उन्होंने गोपालन इसलिए किया है ताकि अपनी खेती को जैविक बना सकें। देसी गाय के गोबर से खाद और गौमूत्र से जीवामृत तैयार कर उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बेहतर बनाया है। वे अपनी 28 बीघा खेती में से पांच बीघा में पूरी तरह जैविक खेती करते हैं। महेश बताते हैं, जैविक खेती के कारण रासायनिक खाद और पेस्टीसाइड पर खर्च होने वाला पैसा बच गया है। इससे लागत भी कम हुई है। हमने किसानों की हरसोला किसान प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाई है। अब इस कंपनी के माध्यम से किसानों के उत्पाद बाजार में उतारना है।

राज्य मंत्री ने सामुदायिक भवनों का किया भूमि-पूजन

ग्रामों का समग्र विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में

जागत गांव हमार, भोपाल।

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर नानो कावरे ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामों के अधोसंरचना विकास के लिये धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। राज्य मंत्री परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम दुगलई, उमरिया एवं मौरिया में सामुदायिक भवन निर्माण के भूमि-पूजन कार्यक्रम का संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि परसवाड़ा क्षेत्र में जिला खनिज निधि से 40 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों को मंजूरी दिलाई गई है। इसके साथ ही परसवाड़ा में चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए 42 औषधालय भवन बनाये जा रहे हैं। सिंचाई सुविधा के विस्तार की चर्चा करते हुए आयुष राज्य मंत्री ने बताया कि 146 करोड़ लागत की लामता सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इस सिंचाई योजना से पाइप लाइन के माध्यम से करीब 55 ग्रामों के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं।

पशुपालन, डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने राज्यपाल से की मुलाकात

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल से राजभवन में पशुपालन, डेयरी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने सौजन्य भेंट की। मंत्री ने राज्यपाल को सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति संबंधी जानकारी दी। मंत्री और चिकित्सकों के दल ने सिकल सेल एनीमिया रोकथाम संबंधी किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम संबंधी किये जा रहे उपायों में और गति लाई जाएगी।

किसानों के कितना काम आएगी केंद्र की पुनर्योजी कृषि योजना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईएआरआई), दिल्ली के प्रमुख वैज्ञानिक और जैविक खेती विशेषज्ञ दिनेश कुमार कहते हैं, जैविक खेती, मिट्टी की संरचना में सुधार और इसकी जैविक तत्वों को बचाए रखने में पर्याप्त मदद करती है। वहीं पानी अवशोषित करने वाली फसलों और जल-कुशल फसलों को एक साथ या वैकल्पिक चक्रों में उपजाने से सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। इससे ऊर्जा का भी संरक्षण होता है।

1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारत को भुखमरी के कगार से वापस खींचकर इसे एक आत्मनिर्भर और एक बड़े खाद्य निर्यातक देश में बदल दिया। लेकिन इस क्रांति के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उत्सर्जक देश भी बन गया। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारत में हर साल दुनिया के भूजल निकासी का एक चौथाई यानी 251 क्यूबिक किमी पानी जमीन से निकाला जाता है। इसमें से 90 फीसदी पानी का इस्तेमाल कृषि के लिए होता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा 2019 के एक अध्ययन से पता चलता है कि देश में गेहूं, चावल और मक्का उपजाने वाले 39 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर पिछले एक दशक में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि देश की कुपोषित आबादी के लिए अन्न चाहिए तो लोगों को प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करना होगा। दुनियाभर के किसान कार्यकर्ता और कृषि अनुसंधान संगठन ऐसे रसायन-रहित खेती के तरीके विकसित कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक तत्वों, फसल चक्र और विविध खेती के तरीकों का उपयोग हो सके। खेती की यह प्रथा सतत कृषि से एक कदम आगे है और मिट्टी व पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का न सिर्फ संरक्षण बल्कि उसे और बेहतर बनाती है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन शाखा के अनुसार, स्वस्थ मिट्टी से बेहतर जल भंडारण में मदद मिलती है। पानी के उपयोग में सुधार से मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों में भी सुधार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि अगर प्रति 0.4 हेक्टेयर जमीन में मृदा कार्बनिक पदार्थ का एक प्रतिशत बढ़ता है, तो इससे जमीन की जल भंडारण क्षमता 75,000 लीटर से अधिक बढ़ जाती है। मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा स्वास्थ्य का एक संकेतक होता है।

भारत में केंद्र सरकार पुनर्योजी कृषि (रिजनरेटिव एग्रीकल्चर) को बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग व लागत को कम करना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और गुजरात जैसे राज्यों ने भी इसे बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन यह देखते हुए कि भारत

में मिट्टी की सेहत अत्यधिक खराब है, क्या यह दृष्टिकोण देश के जल संकट को कम करने में मदद कर सकता है?

दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की गंभीर और व्यापक कमी है। सीएसई के शोधकर्ताओं ने पुनर्योजी कृषि के लाभों और पानी की उपलब्धता के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों और किसानों से बात की। इसका निष्कर्ष था कि पानी बचाने में पुनर्योजी कृषि की भूमिका को समझने के लिए अभी और ठोस अध्ययन की आवश्यकता है। इस शोध के वैज्ञानिक निष्कर्ष भविष्य के नीतिगत उपायों और पहल को लागू करने में भी मदद करेंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईएआरआई), दिल्ली के प्रमुख वैज्ञानिक और जैविक खेती विशेषज्ञ दिनेश कुमार कहते हैं, जैविक खेती, मिट्टी की संरचना में सुधार और इसकी जैविक तत्वों को बचाए रखने में पर्याप्त मदद करती है। वहीं पानी अवशोषित करने वाली फसलों और जल-कुशल फसलों को एक साथ या वैकल्पिक चक्रों में उपजाने से सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। इससे ऊर्जा का भी संरक्षण होता है।

आईसीएआर-आईएआरआई और अन्य कृषि संस्थानों के अनुसार, ये प्रथाएं अक्सर जैविक किसानों द्वारा अपनाई जाती हैं। इन प्रथाओं में फसल चक्र में बदलाव, खेत में अवशेषों को छोड़ना और सूक्ष्म सिंचाई शामिल है। इससे बेहतर जल संरक्षण होता है। हालांकि अब तक पुनर्योजी कृषि की जल बचत क्षमता पर कोई संरचित अध्ययन नहीं किया गया है। जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना इस अभ्यास पर देश का सबसे लंबा प्रयोग है, जो 2004 से चल रहा है। इसे आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मेरठ द्वारा संचालित किया जाता है। हालांकि यह भी जल दक्षता को मापन नहीं करता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने हाल ही में इस विषय पर एक अध्ययन शुरू किया है, लेकिन इसका डेटा अगले तीन या चार साल तक उपलब्ध नहीं होगा।

संतुलित आहार निर्धारण से डेयरी पशुओं में बढ़ाए दूध की मात्रा

» डॉ. सोनू कुमार यादव
» डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा
» डॉ. राहुल चैरसिया
» डॉ. मनीष पांडे
» डॉ. प्रमोद शर्मा

-पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश

भारत में प्राचीनकाल से पशुपालन किया जाता रहा है। इसमें मुख्यत: गाय, भैंसे जैसे दुधारू पशुओं को दूध उत्पादन की दृष्टि से पाला जाता है। पशुओं में दूध की मात्रा और गुणवत्ता उनको खिलाएं जाने वाले आहार पर निर्भर करती है। यदि पशुपालक पयाप्त मात्रा में पशु को संतुलित आहार जिसमें सूखा चारा, हरा चारा और इसके अलावा दलिया, गुड़ या कोई अन्य प्रकार का पौष्टिक आहार दे रहे हैं तो उसमें इसकी मात्रा का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संतुलित आहार का तात्पर्य यह है कि ऐसा आहार, जिसमें सभी अवयव निर्धारित मात्रा में हो। संतुलित आहार से पशु स्वस्थ तो रहते ही है, साथ ही उनकी दूध देने की क्षमता में भी सुधार होता है।

संतुलित आहार क्या है ?: संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जो किसी विशेष पशु की 24 घंटे की निर्धारित पौषाणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का विशेष अनुपात सही मात्रा में शामिल हो। पशु को संतुलित आहार देते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं-

-पशु को स्वादिष्ट एवं सुपाच्य आहा देना चाहिए।

-विषैला, सड़ा-गला, दुर्गंध युक्त व अखाद्य पदार्थों से बना नहीं होना चाहिए।

पशुओं में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता: गाय एवं भैंसों में शुष्क पदार्थ की खपत प्रतिदिन 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 400 किलोग्राम वजन की गाय एवं भैंस को रोजाना 10-12 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इस शुष्क पदार्थ को हम चारे और दाने में विभाजित करें तो शुष्क पदार्थ का लगभग एक तिहाई हिस्सा दाने के रूप में खिलाया जाना चाहिए। पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार का 2/3 भाग मोटे चारे से तथा 1/3 भाग दाने के मिश्रण द्वारा मिला कर तैयार करना चाहिए।

हरे चारे से बढ़ती है दूध की मात्रा: हरे चारे की पाचनशीलता सूखे चारे से अच्छी होती है एवं पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। हरा चारा दूध का उत्पादन बढ़ाता है। इसमें सूडान घास, बाजरा, ज्वार, मकचरी, जई, बरसीम तथा लूसनज आदि शामिल हैं। यदि पशु आहार में हरा चारा शामिल है तो पौष्टिक मिश्रण में 10-12 प्रतिशत पाचक प्रोटीन होनी चाहिए। वहीं यदि हरा चारा नहीं है तो दाने में इसकी मात्रा कम से कम 18 प्रतिशत होनी चाहिए।

पशुओं को प्रति 100 कि.ग्रा. शरीर भार पर 8-10 ग्राम खाने का नमक प्रतिदिन देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत खनिज मिश्रण आहार में मिला कर देना चाहिए।

पशुओं के आहार का वर्गीकरण: पशु के आहार की मात्रा का निर्धारण उसके शरीर की आवश्यकता व कार्य के अनुरूप तथा उपलब्ध भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्वो के आधार पर गणना करके किया जाता है, लेकिन पशुपालकों को गणना कार्य की कठिनाइयों से बचाने के लिए पशुओं में संतुलित आहार की गणना के लिए थम्ब रुल को अपनाना अधिक सुविधा जनक माना जाता है। इसके अनुसार हम मोटे तौर पर व्यस्क दुधारू पशु के आहार को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं-

दूध उत्पादन के लिए आहार: उत्पादन आहार, पशु आहार की वह मात्रा है जिसे कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के लियें 1 किलो दाना (सांद्र आहार) तथा भैंस को प्रत्येक 2 लीटर दूध के लिये 1 किलो दाना दें। यदि हर चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हर 10 किलो अच्छे किस्म के हरे चारे को देकर 1 किलो दाना कम किया जा सकता है। इससे पशु आहार की कीमत कुछ कम हो जाएगी और उत्पादन भी ठीक बना रहेगा। पशु को दुग्ध उत्पादन तथा जीवन निर्वाह के लिए साफ पानी दिन में कम से कम तीन बार जरूर पिलायें।

गर्भावस्था के लिए आहार: पशु की गभज्वस्था में उसे 5वें महीने से अतिरिक्त आहार दिया जाता है क्योंकि इस अवधि के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी के साथ होने लगती है। अत: गभज् में पल रहे बच्चे की उचित वृद्धि व विकास के लिए तथा गाय भैंस के अगले ब्यांत में सही दुग्ध उत्पादन के लिए इस आहार का देना बेहद जरूरी है। 5 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

पशुओं का संतुलित दाना मिश्रण कैसे बनाएं: गाय या भैंस का संतुलित दाना मिश्रण बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दाना मिश्रण बनाने में जो चीजें काम में ली जा रही है वे पौष्टिक हो और सुपाच्य हो तथा दाना मिश्रण में काम आने वाली चीजें आसानी से उपलब्ध हो और सस्ती भी हो ताकि कम लागत में पौष्टिक दाना मिश्रण (सांद्र आहार) तैयार किया जा सके।

मृदा परीक्षण: क्यों, कैसे और इसका प्रभाव

» डॉ. रोबिन कुमार
» डॉ. देव नारायण यादव
» डॉ. अजय कुमार बहेलिया

-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविघालय, कुमारगंज, अयोध्या

मृदा जीवन्त जीवाणुओं का एक निर्जीव समूह है जो कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के जीवन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता रखती है। मृदा को स्वस्थ रखना तथा उपजाउ रखने के साथ-साथ मूल्यांकन करना न किसी मृदा के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। मृदा का स्वास्थ्य ही मनुष्य के स्वस्थ आहार का प्रारम्भिक स्तर है। इसी क्रम मे कहा गया है कि श्वस्थ मृदा, स्वस्थ धरा, परन्तु वर्तमान प्रवेश में मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता को गम्भीरता से न होने के कारक अनेकों प्रकार की आधुनिकता एवं मानव समाज की असंवेदनाशीलता के साथ किसानों द्वारा जाने अनजाने में किये गये विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे- रासायनिक खादों तथा दवाओं का अन्धाधुन्ध प्रयोग, अधिक उत्पादन वाली किस्में , शहरीकरण , दुषित जल का प्रयोग , फसल अवशेषों का उचित प्रबंध न होना, फसल चक्रों एवं फसलों के चयन के साथ - साथ आधुनिक भारी-भरकम वाहनों आदि का प्रयोग है ।

क्यों जरूरी है मृदा परीक्षण ?: सामान्यता: मृदा परीक्षण करने बहुत सी वजह है परन्तु मुख्य रूप से तीन वजहों को आधार माना जा सकता है जो कि निम्न प्रकार है:-

1. सघन खेती के कारण मृदा में उत्पन्न विकारों की जानकारी एवं सुधार के लिए। **2.** मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी के लिए। **3.** मृदा में बोये जाने वाली फसल हेतु पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा तथा उनके की जानकारी के लिए।

मृदा नमूना लेने की प्रचलित विधि:- वी आकार विधि बहुचर्चित, बहुप्रचलित तथा आसान विधि है जो कि किसान भाई बहुत ही सुलभता से प्रयोग में ला सकतें हैं। इस विधि में एक एकड क्षेत्र में लगभग 8 से 10 स्थानों से श्टश् आकार के 15 सेटी मीटर गहरे गडढे बनाये जाते है। जिसके उपरान्त खुरपी के प्रयोग से वी के आकार के किनारों से एक सेमी मोटी परत खुर्च कर साफमृदा को थैले या पॉलिथीन बैग में नमूने के रूप में जमा कर लेते है। सभी 8 - 10 स्थानो से इसी प्रकार प्राप्त नमूनो को जमा कर एक पॉलिथीन सीट पर संयुक्त नमूना बनाने के लिए मृदा नमूनों मे उपस्थित अवशेषों जैसे- कंकड, पत्थर, घास पत्तियों आदि को चुनकर निकाल लेने के बाद नमूने को पॉलिथीन सीट पर गोलाकार रूप में फैलाकर चार बराबर-बराबर हिस्सों में बॉट लेते हैं।

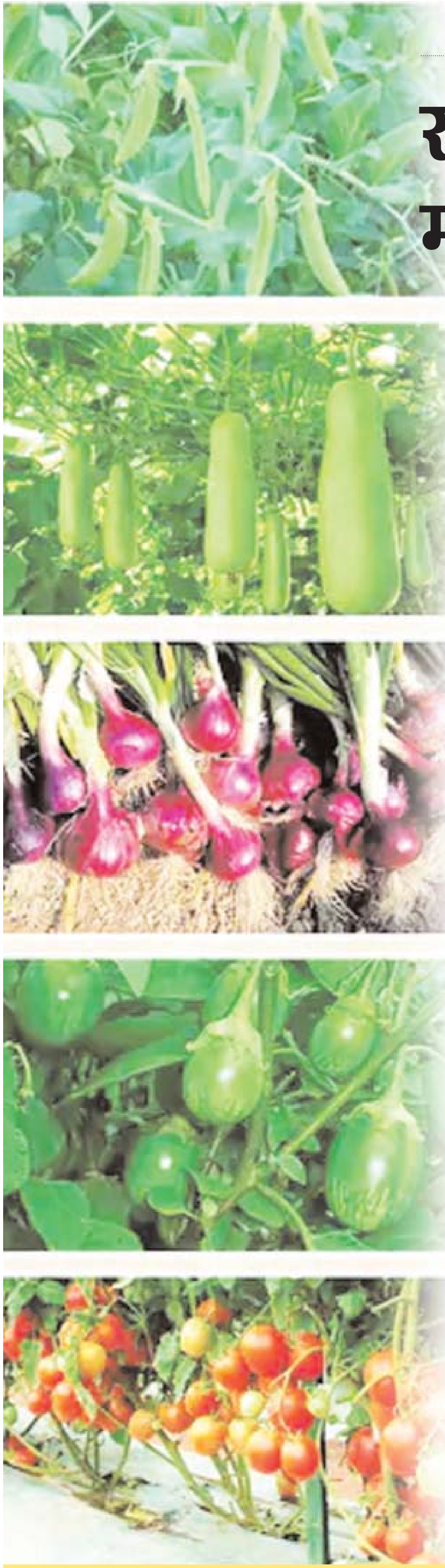

डबल पोस्ट ग्रेजुएट किसान ने पिता से 2 एकड़ खेत लिया

सब्जी की खेती के साथ करते हैं मत्स्यपालन, आमदनी लाखों में

जागत गांव हमार, बैतूल। सतीष साहू

किसान के बेटे ने दो बार पीजी किया। पिता को लगा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन उस लड़के के मन की बात तो वो खुद ही जानता था। उसने अपने पिता की राह चुनी और खेती करने लगा। पिता से थोड़ी जमीन उधार मांगी और उसका प्रयोग इतना सफल रहा कि पिता ने उसे सारी जमीन दे दी। फिर उसने नई राह पकड़ी उस राह पर भी सफलता पाई और अब वो किसान हर साल 10 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहा है। अनिल अपने परिवार के साथ बैतूल में रहते हैं। उनके पास 10 एकड़ जमीन है। बचपन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक उन्होंने अपने पिता को खेती करते हुए देखा था। वे जानते थे कि खेती से पिताजी इतना कमा लेते हैं कि घर चल जाता है, लेकिन उसमें लाभ की गुंजाइश न के बराबर थी। कॉलेज जाने के बाद अनिल ने पहले बॉटनी विषय में एमएससी फिर इतिहास में एमए किया। अनिल बताते हैं कि मेरी पढ़ाई को देखकर सबको लगता था कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी किसी नौकरी के लिए ट्राय तक नहीं किया।

ऐसे शुरू हुआ खेती का सफर

एक कॉलेज से लौटते हुए अनिल ने अपने पिता से कहा कि पापा आप मुझे अपनी 10 एकड़ जमीन में से दो एकड़ जमीन उपयोग के लिए दे दो। मैं इसमें सब्जी उगाना चाहता था। कॉलेज जा रहे अपने बेटे की यह बात सुनकर अनिल के पिता को अचरज तो हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि पढ़ाई के दौरान किसान का बेटा किसानी करना चाहता है। उन्होंने सहज ही अनिल को उसी समय कमिटमेंट कर दिया कि तुम दो एकड़ जमीन में सब्जी उगा सकते हो। अनिल बॉटनी से पढ़ाई कर रहे थे तो वो खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में भी जानते थे। इतनी रिसर्च कर चुके थे कि बैतूल के वेदर में कौन सी सब्जी फायदा का सौदा बनेगी। अनिल ने खूब मेहनत की और पहली ही फसल में खासा मुनाफा कमाया। ताजी सब्जियां होने के कारण मंडी के व्यापारी हाथों-हाथ ले लेते थे। लाभ बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। फिर अनिल ने अपने पिता से और जमीन मांगी तो पिता ने सहर्ष अनुमति दे दी। अब दस एकड़ जमीन पर अनिल सब्जियां उगाकर फुल टाइम किसान हो चुके थे। हजारों से बढ़कर उनकी आय लाखों में पहुंच गई थी।

आसान नहीं थी मछली की खेती

अनिल बताते हैं कि मछली की खेती आसान नहीं थी। इसमें बहुत परेशानियां आईं। मैंने पढ़ा था कि देश में बंगाल की मछली काफी प्रसिद्ध है। मैंने वहां से मछली के अंडे लाकर यहां मछली पालन की सोचा। कोलकाता गया और वहां से मछली के अंडे खरीदे, लेकिन कोलकाता और बैतूल के मौसम में काफी अंतर होने के कारण वे मर जाते थे। पहली बार लगा कि मैंने लापरवाही बरती होगी, फिर अच्छे से कंटेनर में मंगवाए, नतीजा वही था। मैंने हार नहीं मानी और सात बार बंगाल से मछली के अंडे मंगवाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मैंने खेत में ही तालाब खुदवाया। एक तरफ सब्जियों की खेती होती थी तो दूसरी तरफ मछली पालन। इसके लिए मैंने बैतूल में मिलने वाली मछलियां खरीदीं। उनकी हैचिंग कराई फिर जैसे ही अंडे में से बच्चे निकलते हैं, उन्हें बेच देते थे या कभी बच्चे बड़े करने के बाद उन्हें मछली बनाकर बेचते थे। यही प्रोसेस अब भी चालू हैं।

ऐसे तैयार होते हैं मछली के अंडे

अनिल ने बताया कि मछली के अंडे तैयार करने के लिए सबसे पहले भारतीय प्रजाति की मेजर कार्प, माइनर कार्प, रोहू, कतला, मृगल को बारिश में एचसीजी हार्मोन इंजेक्ट करके टैंक में डालते हैं। ये मछलियां 6 से 7 घंटे में ब्रीडिंग करती हैं। इनके अंडे इकट्ठा करके दूसरे टैंक में डालते हैं। इसके बाद इनकी हैचिंग की जाती है। हैचिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अंडे से बच्चों को विकसित किया जाता है। इसके बाद 18 से 20 घंटे में बच्चा निकलता है। 72 घंटे बाद बारीक बच्चा, जिसे जीरा कहा जाता है, वह निकलता है। अब वह बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी इन्हें बड़ा करके भी बेचते हैं। जीरा इसलिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे का आकार जीरे के दाने जितना बड़ा होता है।

फ्राई लिंक 500 रुपए प्रति हजार बिकता

फिंगर 3 रुपए प्रति नग के हिसाब से बिकता है। जीरा पालन में बहुत चुनौतियां मध्यप्रदेश में मछली का जीरा पालन करने में सबसे बड़ी चुनौती यहां का बदलता हुआ मौसम है। दरअसल, जीरा पालन के लिए एक जैसे टेम्प्रेचर की जरूरत होती है, लेकिन बैतूल में मौसम बदलता रहता है। ज्यादा सर्दी पड़ने पर जीरा बर्बाद होने लगता है। ठंड के मौसम में तापमान काफी कम होने से नुकसान उठाना पड़ता है। मैं खुद ही मछली पालन को लेकर काफी शोध कर चुका हूं। मुझे मालूम है कि जीरा पालन करने के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए पॉड और तालाब की डिजाइन खुद ही तैयार किया है। इस तरह के सिस्टम बना दिए हैं कि मछली को सूटेबल टेम्प्रेचर मिल सके।

अलग-अलग तरीके के होते हैं टैंक

अनिल ने बताया कि मछलियों को ब्रीडिंग, हैचिंग और फिर बड़ा करने के अलग-अलग प्रकार और आकार के टैंक हैं। इनमें ब्रीडिंग टैंक, इनकुबेशन टैंक, नर्सरी पौंड शामिल हैं। ब्रीडिंग टैंकों में नाम से ही पता लग रहा है कि मछलियों की ब्रीडिंग करवाई जाती है। इनकुबेशन टैंकों में अंडे सहेजे जाते हैं। टैंको में बारिश के अलावा अन्य दिनों में पानी को नदी की तरह बहाव दिया जाता है, ताकि मछली को पानी बहता हुआ लगे। बारिश का अहसास कराने के लिए टैंकों में कृत्रिम बारिश कराने के लिए पाइपों में छेद करते हैं, ताकि मछली को बारिश का मौसम लगे।

सब्जियों का भी कर रहे उत्पादन

मछली उत्पादन के अलावा भी अनिल आधुनिक तरीके से सब्जी का उत्पादन करते हैं। हालांकि, वे थोड़ी मात्रा में ही सब्जी-फल उगाते हैं, जिससे उन्हें अधिक फायदा होता है, जैसे ककड़ी, तरबूज और गन्ना आदि। अनिल पीले तरबूज भी उगाते हैं, जो बैतूल में खासा लोकप्रिय है। पीले तरबूज को तो लोग हाथों-हाथ खरीद लेते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत मीठे होते हैं।

-सरसों से लहरा रहा बालाघाट जिले का नक्सल क्षेत्र

सरसों की जैविक खेती से नई पहचान बना रहे किसान

जागत गांव हमार, बालाघाट।

जिले का दक्षिण बैहर व लांजी क्षेत्र पुराने दौर की तरह आज भी नक्सली गतिविधियों से दहल रहा है। जबकि एक समय ऐसा भी था कि यंहा के मजदूर किसान नक्सली हिंसा से कांपते हुए महानगरों की ओर तेजी से पलायन कर रहे थे, क्योंकि आए दिन नक्सलियों की वारदातों से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो रहा था। परंतु पुलिस की सक्रियता और अच्छे तालमेल के चलते इन क्षेत्रों में नक्सली गविविधियों पर पूर्व की भांति काफी अंकुश लग चुका है और अब क्षेत्र के किसान पलायल की जगह, गांव में ही खेती किसानी करके गुजर बसर कर रहे हैं। मप्र का बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला है, यंहा पर सरसों की खेती कम ही होती है। यहां कुछ ईलाके ऐसे भी हैं जहां खरीफ और रबी में भी धान का उत्पादन किया जाता है। परंतु कुछ ईलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ खरीफ की ही फसल होती है और रबी के सीजन में भूमि पड़त रह जाती थी। ऐसे में यहां के किसानों ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाते हुए रबी के सीजन में धान की जगह, तिलहनी फसलो की ओर फोकस किया और सरसों और अलसी के उत्पादन को बढ़ावा देने लगे।

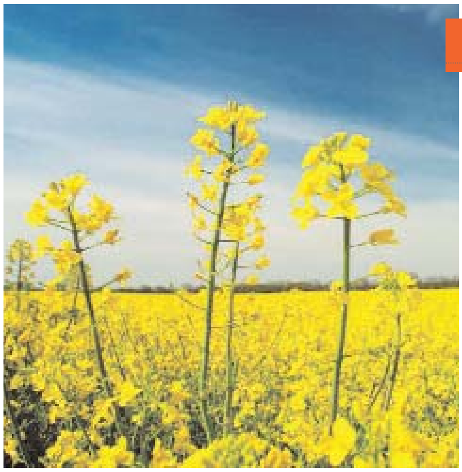

सरसों का बढ़ा रकबा

नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र के किसानों ने सरसों के उत्पादन में रकबा भी बढ़ा लिया है। यहां पर किसान साल भर में अच्छे से धान की फसल नहीं लगा पाते थे और जितनी धान की खेती होती थी उससे उनका जीवन यापन बमुश्किल ही हो पाता था। किंतु अब धान लगाने के पश्चात नवम्बर में जब धान की फसल कटती है तब किसान भी खाली हो जाते हैं और खेती भी। इसलिए यंहा के किसानों ने सरसों की खेती करने का मन बनाया है और वे अब सरसो की खेती कर रहे हैं।

सरसों के पीले पन से सजा क्षेत्र

यदि कोई किसान अपने खेत में सरसों लगाता भी था तो एक एकड़ में बमुश्किल 8 से 10 क्विंटल सरसों होती थी। लेकिन पोंडी ग्राम के किसानों ने जैविक खाद का प्रयोग कर उन्नत किस्म की श्री जी सरसों की खेती करके अपना भाग्य भी आजमा लिया है। जिन्होंने कम स्थान में कम समय में और लागत में भरपूर सरसों की फसल का उत्पादन किया। तभी से अन्य किसानों ने भी सरसों के उत्पादन में अपना ध्यान आकर्षित किया है और वर्तमान में संपूर्ण दक्षिण बैहर, उकवा, लांजी और बिरसा क्षेत्र सरसों के पीले पन से सजा हुआ नजर आता है।

किसानों को अमरूद की उत्तम तकनीकि एवं नयी प्रजाति के विषय में दी गई जानकारी

फल अनुसंधान केन्द्र रीवा में मनाया गया अमरूद दिवस

जागत गांव हमार, रीवा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के निर्देशन में फल अनुसंधान केन्द्र रीवा में गत दिवस कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस. के. पयासी के मार्गदर्शन में अमरूद दिवस मनाया गया । इस अवसर पर रीवा ब्लाक के भारी संख्या में किसानों को अमरूद की उत्तम तकनीकि एवं नयी प्रजाति के विषय में जानकारी फल अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. यू. एस. बोस, डॉ. टी. के. सिंह एवं सुधीर सिंह द्वारा जानकारी दी गई । अमरूद में आने वाली बीमारियों एवं कीटों के विषय में डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया । इस अवसर पर अशोक कुमार मिश्रा, आर वी तिवारी एवं गौरव नामदेव उपस्थित रहे ।

कृषि विज्ञान केंद्र ने खेती पर दिया प्रशिक्षण

प्राकृतिक खेती को बताया वर्तमान की आवश्यकता

जागत गांव हमार, टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ ने गांव कोडिया, ग्राम पंचायत दरगाय कला में जलवायु समुत्थानशील राष्ट्रीय नवाचार परियोजना अंतर्गत किसानों/महिलाओं को प्राकृतिक खेती पर डॉ. बीएस किरार - प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. आरके प्रजापति- वैज्ञानिक, जयपाल छिगारहा ने व्याख्यान दिया। प्राकृतिक खेती पर जागरूकता के तहत वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती को वर्तमान की आवश्यकता बताया, क्योंकि वर्तमान में सब्जियों, फलों एवं खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में असंतुलित एवं अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक उर्वरक, दवायें एवं शाकनाशी दवायों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे मनुष्यों में बहुत सी छोटी बीमारियां अत्याधिक संख्या में पनप रही हैं। साथ ही भूमि जल एवं वायु दूषित होती जा रही है। इन सबका समाधान प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ही है। प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, संजीवनी के निर्माण और उपयोग का तरीका बताया गया। बीजामृत के घोल से बीजोपचार किया जाता है और घनजीवामृत को गाय के गोबर, मूत्र, गुड़, वेसन एवं पीपल/बरगद के पेड़ के नीचे की 250 ग्राम मिट्टी का मिश्रण बनाकर तैयार किया जाता और खेत में डाला जाता है।

अंतरवर्तीय फसलें बोना चाहिए

जीवामृत को गाय का गोबर, मूत्र, गुड़, वेसन एवं पेड़ के नीचे की मिट्टी को पानी में घोलकर तैयार करने के एक सप्ताह बाद खड़ी फसल में छिड़काव करना या सिंचाई के साथ देना चाहिए। प्राकृतिक खेती में खेतों की कम जुताईयां की जाती हैं और दो कतारों के बीच में घास-फूस एवं पत्तियों से आच्छादन (मल्चिंग) करना चाहिए और मुख्य फसल के साथ सहायक फसल अंतरवर्तीय फसलें बोना चाहिए।

कर रहे प्राकृतिक खेती

कीट प्रबंधन के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्नेयस्त्र आदि का घोल तैयार कर फसलों में चूसक एवं काटने वाले कीट प्रबंधन के लिए समय-समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी गयी कि प्रत्येक किसान को अपने रकबा के 10 से 20 प्रतिशत तक भूमि पर प्राकृतिक खेती से सब्जियां एवं अनाज का उत्पादन कर अपने परिवार को उत्तम स्वास्थ्य बनाने और शरीर से बीमारियां दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रशिक्षण में रबी सब्जियों में लगने वाले कीट व्याधियों के प्रबंधन की जानकारी दी गयी।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

मंदसौर। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म की स्थापना की जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को अच्छी अनुवांशिक गुणों की कलोर/पाडी (हीफर) सुगमता से उपलब्ध हो सकें। ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फर्म अंतर्गत उच्च अनुवांशिक गुणों के 200 भारतीय नस्ल गाय/भैसं (गिर, साहीवाल, विदेशी संकर नस्ल, जर्सी, एच, एफ/मुर्रा, जाफरवादी) की प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु शेड निर्माण, उपकरण तथा उक्त नस्लों के संरक्षण एव क्रय हेतु लगभग 4.50 करोड की आवश्यकता होगी, जिसमें से 50 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जावेगी। पात्र इच्छुक हितग्राही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की विस्तृत दिशा निर्देशों के लिये विभाग की web site-www.dahd.nic.in पर जाएं तथा अपने प्रकरण तैयार कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंदसौर को जमा करावें ।

बड़वानी में पशु बाजार पर लगे प्रतिबंध को कलेक्टर ने हटाया

जागत गांव हमार, बड़वानी।

कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जिले में लंपी वायरस के मद्देनजर लगे हुए पशु बाजार के प्रतिबंध को हटा दिया है। लेकिन उन्होंने यह निर्देश दिया है कि हाट बाजार में पशुओं को टीकाकरण के पश्चात ही ले जाया जाए । उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने 14 सितंबर 2022 को लंपी वायरस के मद्देनजर जिले में धारा 144 के तहत पशु बाजार को प्रतिबंधित किया था। जिले में लंपी वायरस का कोई एक्टिव केस नहीं होने तथा समस्त पशुओं का टीकाकरण होने से उन्होंने पशु बाजार पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि हाट बाजार में पशुओं को टीकाकरण के पश्चात भी ले जाया जाए ।

एक जिला एक उत्पाद के तहत 100 किसानों के एफपीओ ने पाई सफलता

डालकी के 8 किसानों की कुल 55 क्विंटल मिर्च का निर्यात

यूरोपीय देशों में निर्यात हुई खरगोन की लाल मिर्च

जागत गांव हमार, खरगोन।

मप्र शासन की बहुद्देशीय योजनानुसार आखिरकार एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित मिर्च की फसल को विदेश में निर्यात करने में सफलता प्राप्त हो गई है। खरगोन में डालकी के किसान उत्पादक समूह टेराग्लेब को यह सफलता मिली है। इसके लिए किसानों ने शुरुआत से ही मिर्च को प्रमुखता देते हुए विदेशों में निर्यात करने का सपना संजोया था। आज वो ही दिन है जब पहली बार किसानों द्वारा उत्पादित मिर्च किसान ही विदेश निर्यात कर रहे हैं। मुम्बई पोर्ट से यूरोपीय देशों में निर्यात हुई है। टेराग्लेब एफपीओ के किसान और फाउंडर बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि आज से तीन वर्ष पूर्व बने इस समूह ने शुरुआत से ही यही कल्पना की थी कि उनकी मिर्च विदेशों में निर्यात हो इस लिहाज से यह उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा दिन है। मुम्बई पोर्ट से डालकी के 8 किसानों की कुल 55 क्विंटल (5.50 टन) मिर्च का निर्यात हो गया है।

केरला की एविटी लेब में 8 सेमपल्स हुए थे पास

समूह के फाउंडर बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि यह सब इतना आसान नहीं था। समूह ने पहले स्टडी कर पता लगाया कि क्यों खरगोन की मिर्च लोकप्रिय होने के बावजूद विदेशों में निर्यात नहीं हो रही हैं। इसका एक कारण विदेशों में प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग है। इन रसायनों का खरगोन के किसान बड़ी मात्रा में करते है। ऐसे रसायनों को अलग कर आईपीएम टेक्नोलॉजी के अनुसार 62 किसानों के साथ 500 एकड़ में मिर्च की खेती प्रारम्भ की। सबसे पहले मिट्टी परीक्षण कर पता लगाया कि मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है। इसके बाद एक जैसी तकनीक अपनाकर उत्पादन प्रारम्भ किया। 62 किसानों के 10 सेम्पल्स केरला की एविटी लेब में टेस्ट भेजे गए जिसमें 8 सेमपल्स पास हो गए। मतलब मिर्च में प्रतिबंधित रसायन जैसे- प्रोपिनोफॉस, ट्रेजोफॉस, क्लोरोपारीफॉस, और मोनोक्रोटफॉस के अलावा भी कई रसायनों से मुक्त पाया गया। ये रसायन अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित है और हमारे जिले की मिर्च में इनकी अत्यधिक मात्रा होने से निर्यात नहीं हो पा रही थी। इसी बात का फायदा अन्य व्यापारी उठाते थे और मिक्स कर दो राज्यों की मिर्च का सीधा निर्यात कर देते थे।

कुछ किसान अरहर प्याज और मूंग जैसी फसलों के बीज भी तैयार कर रहे

टेराग्लेब समूह किसानों को मिट्टी परीक्षण से लेकर बीजों के अलावा संबंधित फसल में उपयोग होने वाली तकनीक तथा अच्छे दाम दिलाने के लिए बाजार और व्यापारी तक उपलब्ध कराने की सुविधा दे रहा है। इसमें किसानों को कृषि उपकरण भी किराए पर उपलब्ध करा रहा है। साथ ही कीटनाशक छिड़काव के लिए समूह ने किसानों को ड्रोन भी उपलब्ध कराए है। समूह के माध्यम से कुछ किसान अरहर प्याज और मूंग जैसी फसलों के बीज भी तैयार कर रहे है।

5 वर्ष पूर्व एफपीओ बनाने के लिए प्रयास शुरू किए

आज से 5 वर्ष पूर्व उद्यानिकी और कृषि विभाग ने किसानों के एफपीओ बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी पीएस ब?गेले ने बताया कि किसानों के एफपीओ बनाने के लिए कई वर्षों से कार्य हो रहे है। इसके लिए अलग-अलग गतिविधियों के लिए पृथक-पृथक कार्यशालाएं आयोजित की गई। गुंटूर सहित अन्य स्थानों पर विजिट और प्रशिक्षण भी आयोजित किये गए। तकनीकी ज्ञान के लिए बाहर से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर किसानों से खेतों में विजिट और चर्चाएं की गई। खरगोन में ऐसा प्रचलन नहीं होने से किसानों में झिझक थी। इसे दूर करने में ब? प्रयास किये गए। शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए यह एफपीओ तैयार होकर। अब विदेश तक अपनी फसल निर्यात कर रहा है। यह उनकी और हमारे प्रयासों के लिए अच्छे संकेत है।

एएचआईडीएफ योजना खोलेगी प्रगति के द्वार

जागत गांव हमार, मंदसौर।

उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने बताया कि ए.एच.आई.डी.एफ. भारत शासन मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान अंतर्गत पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य दूध, अण्डा एवं मांस के उत्पादन को बढ़ावा देना असंगठित उत्पाद को संगठित कर बाजार उपलब्ध कराना एवं इनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर निर्यात बढ़ाना है, ताकि उत्पादकों को सही कीमत, उपभोक्ता को उत्तम सामग्री, बढ़ती आबादी की प्रोटीन आवश्यकता की पूर्ति, कुपोषण का निराकरण एवं उद्यमिता को विस्तार देकर नवीन रोजगार सृजन हो सके।

ए.एच.आई.डी.एफ योजना में यह लाभार्थी निधि का लाभ ले सकतें है ङ्क व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनी, किसान उत्पादक संगठन, कंपनी अधिनियम 8 में शामिल कंपनी। निधि के तहत निम्न गतिविधियां शामिल रहेगी। दुग्ध प्रसंस्करण इकाई एवं उत्पाद डाइवर्सिफिकेशन । मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद निर्माण जैसे- आइसक्रीम यूनिट, चीज निर्माण इकाई, फ्लेवर्ड दूध निर्माण इकाई, दूध पाउडर निर्माण इकाई। मांस प्रसंस्करण इकाई (भेड़ , बकरी एवं कुक्कुट मांस प्रसंस्करण) पशु आहार संयत्र की स्थापना- इसके अंतर्गत 1. छोटे, मध्यम एवं बड़े पशु आहार की स्थापना, 2. कुल मिश्रित राशन निर्माण इकाई, बायपास प्रोटीन इकाई, खनिज लवण इकाई, साइलेज निर्माण इकाई। गौ-भैंस वंशीय, भेड़ एवं बकरी पशुओं की नस्ल सुधार तकनीक एवं नस्ल संवर्धन प्रक्षेत्र की स्थापना करना। जिले के समस्त किसान उत्पादक संगठन एवं व्यक्तिगत उद्यमियों से अपील की जाती है कि वे अपना प्रकरण ahidf.udyamimitra.in पोर्टल पर दर्ज करावें। आवेदन भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो श्री विकास (सेडमेप) मो.न. 9599937207 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

शीतलहर और पाले की वजह से फसल बर्बाद होने का भय हुआ कम

वैज्ञानिकों ने खोजा आलू में झुलसा रोग का उपाय

जागत गांव हमार, नई दिल्ली।

एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। सर्दी की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शरीर को गर्म रखने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं, ठंड ने किसानों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। खास कर आलू की खेती करने वाले किसानों को शीतलहर और पाले की वजह से फसल बर्बाद होने का भय सता रहा है। किसानों को लग रहा है कि इसी तरह से पाले का प्रकोर जारी रहा तो आलू का प्रोडक्शन भी प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठना पड़ सकता है। हालांकि, इससे बचाव के लिए किसान तरह- तरह के जतन कर रहे हैं। आलू की खेती करने वाले किसान अपनी फसलों की हल्की सिंचाई कर रहे हैं, ताकि खेत का तापमान बराबर बना रहे और फसल का बचाव हो सके।

50 हजार हेक्टेयर रकबे में आलू की खेती कर रखी है

बता दें कि हाथरस जिले में किसान आलू की खेती प्रमुखता से करते हैं। इस साल जिले में किसानों ने 50 हजार हेक्टेयर रकबे में आलू की खेती कर रखी है। यानी किसानों का मोटा पैसा फसल में लगा हुआ है। वहीं, स्थानीय किसानों का कहना है कि कुछ खेतों में झुलसा के चलते आलू के पौधों की पत्तियां, तना व जड़ें काली पड़ने लगी हैं। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सही समय पर अगर इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो फसल बर्बाद होने का खतरा है।

किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया है

डा. एसआर सिंह ने बताया कि ठंड और अधिक नमी की वजह से आलू की फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना बढ़ गई है। इस बीमारी से आलू के पौधे की पत्तियां झुलस जाती हैं। ऐसा लगता है, जैसे पत्तियां जल गई हों। साथ ही झुलसा रोग लगने से आलू का उत्पादन भी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया है।

फसल की हल्की- हल्की सिंचाई करते रहें

कृषि वैज्ञानिक एसआर सिंह ने बताया कि फाइटोफ्थोरा नाम के फफूंद की वजह से आलू के पौधों में अधिक नमी की वजह से झुलसा रोग होता है। अगर समय से इसकी रोकथाम न की जाए तो पूरी फसल खेत में ही झुलस जाती है। एसआर सिंह ने बताया कि झुलसा रोग से बचाव के लिए किसान 3 ग्राम कर्जेट एमआर्ट व डाई मेथोमार्फ दवा एक लीटर पानी में मिलाकर आलू फसल के ऊपर छिड़काव करें। साथ ही पाले से बचाव के लिए खेत की नमी बनाए रखें। फसल की हल्की- हल्की सिंचाई करते रहें।

इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल को दी जाएगी मंजूरी

नैनो-डीएपी मंजूरी जल्द, आधा हो जाएगा फर्टिलाइजर का खर्चा

जागत गांव हमार, नई दिल्ली

किसानों के लिए एक खुशखबरी है। बहुचर्चित नैनो-डीएपी की आधिकारिक मंजूरी अगले एक से दो दिनों में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सुझाव दिया है कि इसे एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से जारी किया जाए। वहीं, जानकारों का कहना है कि नैनो-डीएपी के मार्केट में आने से किसानों को काफी फायदा होगा। उनका फर्टिलाइजर पर होने वाले खर्चा आधा हो जाएगा।

उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि जैव-सुरक्षा और टॉक्सिसिटी टेस्ट से पता चला है कि नैनो-डीएपी सुरक्षित है। ऐसे में इसकी अंतिम मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल दोनों ने नैनो-डीएपी को मंजूरी देने के लिए कहा है। दोनों को मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि आईसीएआर ने कहा है कि एक साल के लिए मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार किसानों को नैनो-डीएपी का व्यावसायिक रूप से खेत में उपयोग करने देगी या इसका उपयोग केवल बीज के लिए किया जाएगा।

कियोस्क से ही कृषि वैज्ञानिकों से बात की जाएगी- मंत्री ने वादा किया कि नैनो-डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) रेगुलर डीएपी से बेहतर होगा, जैसे नैनो यूरिया रेगुलर यूरिया से बेहतर था। उन्होंने खेती के लिए इन नए विचारों के साथ आने के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और किसानों से इन नए उर्वरकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने को कहा। उन्होंने किसानों और खुदरा विक्रेताओं से ऑनलाइन बात की और सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) टेलीकांफ्रेंस की सुविधा स्थापित करें, ताकि किसानों को कृषि संबंधी कोई समस्या होने पर कियोस्क से ही कृषि वैज्ञानिकों से बात की जा सके।

किसान इन केंद्रों पर अन्य सलाह प्राप्त कर सकते हैं

इफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि अगले खरीफ सीजन में नैनो-डीएपी को 600 रुपये प्रति 500 मिलीलीटर की बोतल में बेचा जाएगा। यह डीएपी के रेगुलर 50 किलो के बैग के समान है, जो अभी (सब्सिडी के साथ) ?1,350 प्रति बैग के हिसाब से बेचा जाता है। मंडाविया ने अलग-अलग राज्यों के चार किसानों और पीएमकेएसके के दो मालिकों से बात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि नैनो-यूरिया जैसे विभिन्न उर्वरक उपलब्ध हैं या नहीं और क्या किसान इन केंद्रों पर अन्य सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना होगा

केंद्र ने उर्वरक कंपनियों से कहा है कि उनकी सभी खुदरा दुकानों, जिनकी संख्या 2 |7 लाख होने का अनुमान है, को पीएमकेएसके कहा जाना चाहिए। साथ हीअपने स्वयं के खर्च पर आधिकारिक डिजाइन और स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मंडाविया ने कहा कि इनमें से लगभग 9,000 कियोस्क पहले से ही जाने के लिए तैयार हैं। सरकार की योजना के अनुसार, इन पीएमकेएसके को उर्वरक, बीज, कीटनाशक और खेती के उपकरण जैसे कृषि-इनपुट प्रदान करने होंगे। उन्हें मृदा परीक्षण सेवाओं की पेशकश भी करनी होगी और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में पीएमकेएसके की शुरुआत की, तो उन्होंने वर्चुअल रूप से एक ही समय में इनमें से 600 केंद्र खोले। मंडाविया को लगता है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक दस लाख से अधिक पीएमकेएसके तैयार हो जाएंगे। बैठक के दौरान, मंडाविया ने किसानों से नैनो-यूरिया जैसी नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहा, ताकि वे पारंपरिक यूरिया का कम उपयोग करें। साथ ही सिर्फ यूरिया और डीएपी का उपयोग करने के बजाय अब बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग मिट्टी की जरूरत के आधार पर किया जा सकता है।

पोषक तत्व को उचित मूल्य पर खरीद सकें

उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग के लाभों के बारे में बात की और कहा कि यह नया उत्पाद नियमित यूरिया की तुलना में सस्ता है, यहां तक कि बिना सरकारी सब्सिडी के भी, और वह इसे अपने खेत पर उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को पारंपरिक यूरिया पर 2,000 रुपये प्रति बैग (45 किलोग्राम) की सब्सिडी देता है, ताकि वे इस पोषक तत्व को उचित मूल्य पर खरीद सकें।

जीएम सरसों डीएमएच 11 पर विवाद

आईसीएआर महानिदेशक ने बयान जारी किया

नई दिल्ली। जीएम विरोधियों द्वारा सरसों किस्म डीएमएच 11 की मंजूरी के संबंध में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मानव और पशु उपभोग पर जीएम फसलों की खपत के जोखिम का आकलन करने के लिए कृषि, स्वास्थ्य सहित आधुनिक और आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली सभी राष्ट्रीय एजेंसियां और सार्वजनिक अनुसंधान प्रणालियां शामिल हैं।

महानिदेशक-आईसीएआर डॉ हिमांशु पाठक ने जीएम सरसों के विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत बयान जारी किया। उन्होंने उल्लेख किया कि जीईएसी द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों डीएमएच 11 और इसकी पैतृक वंशावलियों को पर्यावरण के लिए जारी करने की हालिया मंजूरी ने बड़े पैमाने पर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। जीएम तकनीक में भारतीय कृषि में बहुप्रतीक्षित क्रांति की आसन्न क्षमता है। विशेष रूप से देश में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन, आवश्यकता और आयात के संबंध में वर्तमान परिदृश्य को देखना महत्वपूर्ण है।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत

घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है। 2021-22 के दौरान, हमने 14.1 मिलियन टन खाद्य तेलों के आयात पर 1,56,800 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें मुख्य रूप से ताड़, सोयाबीन, सूरजमुखी और कनोला तेल शामिल हैं, जो भारत के 21 मिलियन टन के कुल खपत के दो-तिहाई के बराबर है।

डीएमएच 11 की उपज अधिक है?

जीएम सरसों किस्म डीएमएच-11 का भारत में कई स्थानों पर सीमित क्षेत्र परीक्षणों में राष्ट्रीय चेक वरुणा के खिलाफ तीन साल तक परीक्षण किया गया है। निर्धारित दिशा-निर्देशों और लागू नियमों के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए फील्ड परीक्षण किए गए थे। डीएमएच 11 ने राष्ट्रीय जाँच की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत अधिक उपज दिखाई। आईसीएआर संस्थान और विश्वविद्यालय 2006 से फंक्शनल जीनोमिक्स एंड जीनोम मॉडिफिकेशन पर नेटवर्क प्रोजेक्ट के माध्यम से 11 संस्थानों को शामिल करते हुए फ्लैक्स, गेहूं और गन्ना के साथ 13 फसलों जैसे कपास, पपीता, बैंगन, केला, चना, अरहर, आलू, ज्वार, ब्रासिका, चावल में जैविक और अजैविक तनाव सहिष्णुता, उपज और गुणवत्ता सुधार जैसे विभिन्न लक्षणों के लिए जीएम फसलों के विकास में निरंतर लगे हुए हैं।

भारत के एग्री और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात 16 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली।

भारत के एग्री और प्रोसेस्ड फूड की दुनिया भर में लगातार मांग बढ़ रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि के बीच इन उत्पादों का निर्यात बढ़त के साथ 17 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ दालों,पोल्ट्री उत्पादों, बासमती चावल में देखने को मिली है. वहीं अनाज फलों और सब्जियों के निर्यात में भी बढ़त दर्ज हुई है। मिनिस्ट्री के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की मदद से वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में पूरे साल के लिए निर्यात लक्ष्य का 74 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।

कितना हुआ कुल निर्यात

सरकार के द्वारा आंकड़ों के अनुसार एग्री और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के चालू वित्त वर्ष के आठ महीनों (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़कर 17.43 अरब डालर तक पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में कुल निर्यात 15.07 अरब डालर के स्तर पर था। इस साल अब तक हुआ निर्यात पूरे साल के लक्ष्य का 74 प्रतिशत है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में एग्री और प्रोसेस्ड फूड के लिए 23.56 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है।

कितना हुआ निर्यात

जारी आंकड़ों के अनुसार अवधि के दौरान ताजे फलों का निर्यात पिछले साल के 95.4 करोड़ डॉलर के स्तर से बढ़कर 99.1 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रोसेस्ड फलों तथा सब्जियों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान तेज बढ़त के साथ 1.31 अरब डॉलर तक जा पहुंचा जोकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान 98.8 करोड़ डॉलर रहा था। दलहन के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49 प्रतिशत की बढोतरी देखी गई है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- अरविंद मिश्र, संपर्क -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)